पटना उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

1977 के कराधान मामला संख्या 13,14 और 15

निर्णय लिया गयाः 17.12.1986

याचिकाकर्तागणः **आयकर आयुक्त**

बनाम

उत्तरदाताः **शंकर लाल बुधिया**

संदर्भित मामलेः

i. (1937) 5 आईटीआर 90 (कल्याणजी विठ्ठलदास बनाम सी.आई.टी.)

ii. (1975) 101 आईटीआर 776 (एससी) (सुरजीत लाल छाबड़ा बनाम सी.आई.टी.)

iii. (1974) 971 आईटीआर 493 (एससी) (सी. कृष्ण प्रसाद बनाम सी.आई.टी.)

iv. (1983) 142 आई.टी.आर. 357 (एम. पी.) (सी.आई.टी. बनाम विष्णु कुमार)

आयकर अधिनियम - क्या हिंदू कानून द्वारा शासित किसी निर्धारिती व्यक्ति की स्थिति केवल उसकी शादी पर (अभी तक बिना किसी मुद्दे के) आई. टी. अधिनियम के तहत एच. यू. एफ. के तहत बदल जाएगी-क्या शादी उस कानूनी स्थिति को बदल देगी, इस सवाल की कसौटी पर परीक्षण किया जा सकता है कि क्या उसकी पत्नी अभी तक अपनी शादी के बाद निर्धारिती द्वारा संपत्ति के किसी भी अलगाव को चुनौती या आपत्ति दे सकती है-हिंदू अविभाजित परिवार में सीमित स्वामित्व की बुनियादी अवधारणाओं में से एक इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट होगी-केवल विवाह अपने आप में अलग संपत्ति और व्यक्तिगत आयकर स्थिति को हिंदू में परिवर्तित नहीं करेगा। अविभाजित परिवार-इस अधिनियम के तहत हिंदू अविभाजित परिवार की अवधारणा एक हिंदू सह-सदस्य से अलग और भिन्न है-एक हिंदू निर्धारिती की अविवाहित बेटी होने के मामले में, यदि उसकी मूल स्थिति एक व्यक्ति की थी, तो वह शादी या महिला मुद्दे के तथ्य से नहीं बदलेगी और यहां तक कि अपनी अलग संपत्ति को आम हॉटस्पॉट में फेंकने से भी नहीं बदलेगी।

आयोजित- हिंदू कानून द्वारा शासित एक व्यक्तिगत निर्धारिती की स्थिति आयकर अधिनियम के तहत एक हिंदू अविभाजित परिवार की स्थिति में नहीं बदलेगी, स्वचालित रूप से उसकी शादी पर और विवाह के बाद निर्धारिती की स्थिति एक व्यक्ति की थी लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार की नहीं।

पटना उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

1977 के कराधान मामला संख्या 13,14 और 15

निर्णय लिया गयाः 17.12.1986

याचिकाकर्तागणः **आयकर आयुक्त**

बनाम

उत्तरदाताः **शंकर लाल बुधिया**

माननीय न्यायाधीश/कोरमः

एस.एस. संधवालिया, मुख्य न्यायाधीश, एस. के. झा और उदय सिन्हा, न्यायमूर्तिगण

सलाहकार/अधिवक्ताः

अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/वादी के लिएः बी.पी. राजगढ़िया और एस. के. शरण, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं/प्रतिवादी के लिएः एस.बी. गडोडिया, पवन कुमार और एल. के. तिवारी, अधिवक्तागण

निर्णय

एस. एस. संधवालिया, मुख्य न्यायाधीश

1. क्या हिंदू कानून द्वारा शासित किसी व्यक्ति की निर्धारिती स्थिति केवल उसकी शादी पर (अभी तक बिना किसी मुद्दे के) आयकर अधिनियम के तहत एक हिंदू अविभाजित परिवार की स्थिति में बदल जाएगी-यह कुछ हद तक पेचीदा सवाल है जो पूर्ण पीठ को इस संदर्भ की आवश्यकता बनाता है।

2. तथ्यों को सापेक्ष संक्षिप्तता के साथ देखा जा सकता है। प्रत्यर्थी-निर्धारिती, श्री शंकर लाल बुधिया, मूल रूप से श्री महाबीर प्रसाद बुधिया के एक बड़े हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य थे। 22 मार्च, 1956 को उक्त परिवार का आंशिक विभाजन हुआ था और उस समय प्रतिवादी नाबालिग था। इसमें उन्हें रांची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, बुधिया ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड और गणपतराय प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड में शेयर आवंटित किए गए और उसके बाद उन्होंने कुछ अन्य अचल संपत्तियों में भी हिस्सेदारी हासिल की। यह आम आधार है कि आंशिक विभाजन की तारीख से, लगभग एक दशक तक, उसके द्वारा मूल्यांकन वर्ष 1966-67 तक एक व्यक्ति की स्थिति में विवरणी दाखिल की गई थी। मूल्यांकन एक व्यक्ति की स्थिति में भी किया गया था।

3. हालाँकि, 9 मार्च, 1966 को अपनी शादी के बाद, निर्धारिती ने दो विवरणी दाखिल की- एक व्यक्ति की स्थिति में और दूसरा वर्ष 1967-68,1968-69 और 1969-70 के लिए एक हिंदू अविभाजित परिवार की स्थिति में। हालाँकि, आयकर अधिकारी ने यह दृढ़ विचार रखा कि इन वर्षों के लिए भी, प्रत्यर्थी-निर्धारिती की स्थिति, अतीत में केवल एक व्यक्ति की स्थिति के समान ही होनी चाहिए। निर्धारिती ने मामले को अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील में लिया जिसमें उन्होंने उत्तराधिकारी आयकर अधिकारी से रिमांड रिपोर्ट मांगी, जिन्होंने बाद में यह विचार व्यक्त किया कि दोनों क्षमताओं के तहत पूरी आय का मूल्यांकन हिंदू अविभाजित परिवार की स्थिति में किया जाना चाहिए। तथापि, अपीलीय सहायक आयुक्त ने यह दृढ़ मत व्यक्त किया कि 22 मार्च, 1956 को बड़े हिंदू अविभाजित परिवार के आंशिक विभाजन पर निर्धारिती द्वारा अर्जित संपत्ति के संबंध में, जब निर्धारिती नाबालिग था और 9 मार्च, 1966 को उसकी शादी के बाद भी, उसकी स्थिति निम्नवत बनी रहेगी - एक व्यक्ति जब तक कि उनके एक पुत्र का जन्म नहीं हुआ। इससे व्यथित होकर, निर्धारिती न्यायाधिकरण में आगे की अपील में आया, जिसने यह कहते हुए उसके पक्ष में निर्णय दिया कि मार्च, 1966 में उसकी शादी के बाद, निर्धारिती एक हिंदू अविभाजित

परिवार का गठन करेगा, भले ही उसका कोई पुत्र पैदा न हुआ हो। तदनुसार उन्होंने अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश को दरकिनार कर दिया और उपरोक्त के आलोक में मामले को निपटाने के लिए उन्हें भेज दिया।

4. आयकर आयुक्त ने कानून के मुद्दे पर न्यायाधिकरण से संदर्भ का दावा किया, जिसे हालांकि अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद आयुक्त ने एक आदेश की मांग के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया और 16 अगस्त, 1978 को खंड पीठ ने निर्देश दिया कि अदालत के फैसले के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न का उल्लेख किया जाएः

> "क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों पर, न्यायाधिकरण कानूनी रूप से यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि विवाह के बाद भी निर्धारिती का दर्जा हिंदू अविभाजित परिवार का था न कि किसी व्यक्ति का?"

5. जाहिर तौर पर इस मुद्दे के महत्व के कारण, यह भी निर्देश दिया गया था कि मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाना चाहिए।

6. चूँकि मेरा दृढ़ता से यह विचार है कि हमारे सामने मूल प्रश्न अब बाध्यकारी और प्रेरक उदाहरण दोनों द्वारा नियंत्रित है, इसलिए सिद्धांत पर किसी भी विस्तृत शोध प्रबंध को शुरू करना अनावश्यक होगा, यदि व्यर्थ नहीं। फिर भी, बहुत हद तक, कल्याणजी विट्ठलदास बनाम सी. आई. टी. [1937] 5 आई. टी. आर. 90 में सर जॉर्ज रैंकिन के संक्षिप्त लेकिन प्रसिद्ध उक्ति को याद करना उपयुक्त लगता हैः 1'"हिंदू अविभाजित परिवार' वाक्यांश का उपयोग कानून में संदर्भ के साथ किया गया है, न कि केवल हिंदू कानून के एक स्कूल के लिए, बल्कि सभी स्कूलों के लिए; और उनके स्वामी मानते हैं कि अधिनियम के व्यापक वाक्यांश 'हिंदू सह-सदस्य' पर चिपकाना एक गलती है, इससे भी अधिक कि अधिनियम के चेहरे पर यह कहना संभव नहीं है कि कोई भी महिला सदस्य नहीं हो सकती है।

7. इस प्रकार यह देखने के बाद कि अधिनियम के तहत एक हिंदू अविभाजित परिवार की अवधारणा एक हिंदू सह-सदस्य से अलग और अलग है, जो वास्तव में एक बहुत ही संकीर्ण अवधारणा है, कोई भी इस संदर्भ में लागू हिंदू कानून के निर्विवाद और मूल नियम की ओर बढ़ सकता है। यह वास्तव में हिंदू कानून के सिद्धांतों पर मुल्ला के आधिकारिक कार्य के अनुच्छेद 340 में इसके संक्षिप्त तत्व से देखा जा सकता हैः

> "340.विभाजन पर अर्जित अंश का हस्तांतरण। विभाजन का प्रभाव सह-अधिवेशन को भंग करना होता है, जिसके परिणामस्वरूप अलग होने वाले सदस्य अपने-अपने हिस्से को अपनी अलग संपत्ति के रूप में रखते हैं, और प्रत्येक सदस्य का हिस्सा उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई सदस्य अपने अन्य सह-भागीदारों से अलग होते हुए अपने पुरुष मुद्दे के साथ संयुक्त रूप से जारी रहता है, तो विभाजन पर उसे आवंटित किया गया हिस्सा उसके हाथों में पुरुष मुद्दे के संबंध में सह-संपत्ति का चरित्र बनाए रखेगा।"

8. उपरोक्त दृढ़ आधार से आगे बढ़ते हुए, कोई भी निर्विवाद तथ्यों और एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण के लिए संक्षिप्त रूप से विज्ञापन दे सकता है जिसे उस पर लागू किया जा सकता है। मान लीजिए कि 1956 के बाद से, पहले के हिंदू संयुक्त परिवार के विभाजन के बाद, निर्धारिती ने अपने हिस्से को अपनी अलग व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में रखा। उस समय, वह नाबालिग था, लेकिन यह विवाद में नहीं है कि बहुमत प्राप्त करने के साथ-साथ कानून और तथ्य दोनों में, उसने कर योग्य संपत्ति को अपनी अलग संपत्ति और एक व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति के रूप में रखा। यह दोहराया जाता है कि 1956 से दस वर्षों के लिए प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने स्वयं एक व्यक्ति की स्थिति में अपनी विवरणी दाखिल की और इस तरह से मूल्यांकन किया गया। इस बात पर कोई विवाद नहीं प्रतीत होता है कि इस अवधि में उन्हें अपनी अलग संपत्ति पर स्वामित्व का पूर्ण और असीमित अधिकार था, न कि

सीमित। क्या विवाह उस कानूनी स्थिति को बदल देगा, इस सवाल के आधार पर परीक्षण किया जा सकता है कि क्या उसकी पत्नी अभी तक विवाह के बाद निर्धारिती द्वारा संपत्ति के किसी भी अलगाव को चुनौती या आपत्ति दे सकती है। स्पष्ट रूप से उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। मान लीजिए, अभी तक, विवाह की कोई संतान नहीं है और भले ही पत्नी को किसी भी अलगाव पर हमला करने का कोई अधिकार न हो, हिंदू अविभाजित परिवार में सीमित स्वामित्व की बुनियादी अवधारणाओं में से एक इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट होगी। इसलिए, इस कसौटी पर भी, केवल विवाह अपने आप में अलग संपत्ति और व्यक्तिगत आयकर की स्थिति को हिंदू अविभाजित परिवार में परिवर्तित नहीं करेगा।

9. यदि उपरोक्त सिद्धांत के लिए प्राधिकार की आवश्यकता थी, तो यह सी. कृष्ण प्रसाद बनाम सी. आई. टी. मनु/एससी/0240/1974 में मौजूद हैः [1974]97 आईटीआर 493 (एससी)। इसमें, सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपत्य कर के उद्देश्यों के लिए एक हिंदू अविभाजित परिवार के दर्जे का दावा करने वाले एकल व्यक्ति के मामले पर विचार कर रहे थे और निम्नलिखित रूप में कहा गया था (पृष्ठ 497 पर):

> "उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान में अपीलार्थी उस संपत्ति का पूर्ण स्वामी है जो विभाजन के परिणामस्वरूप उसके हिस्से में आ गई थी और वह इसे अपनी इच्छानुसार निपट सकता है। माना जा सकता है कि ऐसी कोई महिला सदस्य मौजूद नहीं है जो उपर्युक्त संपत्ति से भरण-पोषण की हकदार हो या जो किसी मृत सह-भागीदार पुत्र को गोद लेने में सक्षम हो। भले ही भविष्य में निर्धारिती-अपीलकर्ता गोद लेकर या अन्यथा परिवार में एक नए सदस्य का परिचय देता है, संपत्ति का उसका वर्तमान पूर्ण स्वामित्व प्रभावित नहीं हो सकता है।"

10. डेक को साफ करने के बाद, अब कोई भी सीधे तौर पर सुरजित लाल छाबड़ा बनाम सी. आई. टी. मनु/एस. सी./0266/1975 में अपने अधिपति के आधिकारिक उच्चारण पर जा सकता हैः[1975]101 आई. टी. आर. 776 (एस. सी.), जो मेरे विचार में, अब निर्णायक रूप से इस मुद्दे को शामिल करता है। अन्य मामलों के अलावा, संबद्ध प्रश्न एक निर्धारिती के संदर्भ में उनके स्वामी द्वारा सीधे विचार के लिए आए, जिसकी पत्नी के अलावा एक अविवाहित बेटी भी थी। यह उसमें निम्नानुसार आयोजित किया गया था (पृष्ठों 795-796 पर):

> "अपीलार्थी का कोई पुत्र नहीं है। उनकी पत्नी और अविवाहित बेटी को कथोके लॉज की आय से उनके द्वारा बनाए रखने का अधिकार था, जबकि यह उनकी अलग संपत्ति थी। उस संपत्ति में उनके अधिकारों का विस्तार इस कारण से नहीं किया गया है कि संपत्ति को पारिवारिक स्थल में फेंक दिया गया था। अपीलार्थी के सह-पक्षकार नहीं हो पुत्र के कारण, उन्हें न तो संपत्ति में जन्म से अधिकार है और न ही इसके विभाजन की मांग कर पुत्र का अधिकार है और न ही वास्तव में अपीलार्थी को किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति को अलग कर पुत्र से रोक पुत्र का अधिकार है। वह कानूनी आवश्यकता या संपत्ति के लाभ के विचार से अनियंत्रित होकर एक पूर्ण मालिक के रूप में इससे निपट सकता है। वह इसे बेच सकता है, इसे गिरवी रख सकता है या इसे उपहार में दे सकता है। यहां तक कि अलगाव के बाद पैदा हुए या गोद लिए गए पुत्र को भी परिवार का हॉटस्पॉट लेना होगा। अलगाव के बाद पैदा हुए, पैदा हुए या गोद लिए गए पुत्र को अलगाव को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।
>
> चूँकि अपीलार्थी का व्यक्तिगत कानून उसे कथोके लॉज का मालिक मानता है और उससे होने वाली आय को उसकी आय के रूप में मानता है, तब भी जब संपत्ति को

परिवार के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया था, आय आयकर से उसकी व्यक्तिगत आय के रूप में प्रभार्य होगी न कि परिवार की।"

11. उपरोक्त से यह कुछ हद तक स्पष्ट होगा कि एक हिंदू निर्धारिती की अविवाहित बेटी होने के मामले में भी, यदि उसकी मूल स्थिति एक व्यक्ति की थी, तो यह विवाह या महिला विवाद के तथ्य से और यहां तक कि अपनी अलग संपत्ति को आम विवाद में डालने से भी नहीं बदलेगा। वर्तमान मामला राजस्व के पक्ष में एक मजबूत आधार पर है क्योंकि, अभी तक, निर्धारिती के पास कोई भी मुद्दा नहीं है-पुरुष या महिला। सी. आई. टी. बनाम विष्णुकुमार भैय्या एम. ए. एन. यू./एम. पी./0120/1983 मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने जो प्रेरक निर्णय दिया है, वह इस प्रकार हैः[1983]142 आई. टी. आर. 357 (एम. पी.), जो कि सुजीत लाल छाबड़ा के आधार एम. ए. एन. यू./एस. सी./0266/1975 का अनुसरण करता हैः[1975]101 आई. टी. आर. 776 (एस. सी.), जैसा कि निम्न परिस्थितियों में देखा गया है (आई. टी. आर. 142 का पृष्ठ 360):

> "वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, जब विभाजन में निर्धारिती द्वारा संपत्ति प्राप्त की गई थी, तो वह एकल सदस्य था और परिवार का गठन नहीं करता था। उनकी स्थिति एक व्यक्ति की थी। इन परिस्थितियों में, उसकी शादी के तथ्य ने स्थिति को नहीं बदला और पुत्र की अनुपस्थिति में, निर्धारिती का व्यक्तिगत कानून उसे विभाजन में प्राप्त संपत्ति का मालिक मानता है और उससे होने वाली आय को उसकी आय मानता है। इसलिए, निर्धारिती एक व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति में मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है और न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित करने में उचित नहीं था कि निर्धारिती अपने विवाह के बाद एक हिंदू अविभाजित परिवार की स्थिति में मूल्यांकन का हकदार था।"

12. पूर्व उद्धृत दो मामलों से, यह कुछ हद तक स्वयंसिद्ध होगा कि यदि विवाह और महिला मुद्दे या मुद्दे भी आयकर के उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत स्थिति को हिंदू अविभाजित परिवार में परिवर्तित नहीं करेंगे, तो यह स्पष्ट है कि बिना किसी मुद्दे के केवल विवाह ही ऐसा कोई परिणाम प्राप्त करने से बहुत दूर होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह मुद्दा अब बाध्यकारी पूर्ववर्ती द्वारा शासित है और संविधान के अनुच्छेद 141 के आधार पर, इस सवाल को छोड़कर कि क्या उपरोक्त दृष्टिकोण किसी भी तरह से अंतिम अदालत के किसी अन्य निर्णय से भिन्न होगा, इस पर आगे कोई चर्चा आवश्यक या संभव नहीं है खुद को इन संकीर्ण मापदंडों के भीतर सीमित पाते हुए। प्रत्यर्थी निर्धारिती की ओर से श्री गडोडिया ने लगभग हताशा के तर्क में यह तर्क देना चाहा कि स्वजीत लाल छाबड़ा के मामले MANU/SC/0266/1975 में व्यक्त विचारः[1975]101 आई. टी. आर. 776 (एस. सी.), सी. कृष्ण प्रसाद के मामले एम. ए. एन. यू./एस. सी./0240/1974 में उनके अधिपति से भिन्न थाः[1974]97 आईटीआर 493 (एससी)। हालाँकि, उस निर्णय को बारीकी से पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि ऐसा कोई भी निवेदन कम से कम आवश्यक नहीं है। उस मामले में, उनके स्वामी मुख्य रूप से इस सवाल पर विचार कर रहे थे कि क्या एक एकल व्यक्ति पहले एक परिवार का गठन करेगा और आयकर के उद्देश्य से एक हिंदू अविभाजित परिवार का गठन करेगा। उन्होंने नकारात्मक में सीमा प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि एक एकल व्यक्ति एक परिवार का गठन नहीं करता है और इसके परिणामस्वरूप हिंदू अविभाजित परिवार होने का कोई विचार भी नहीं होगा। यह निम्नानुसार देखा गया था (पृष्ठ 496 पर):

> "उपरोक्त से यह पता चलता है कि 'परिवार' शब्द हमेशा एक समूह को दर्शाता है। व्यक्तियों की बहुलता परिवार की एक अनिवार्य विशेषता है। एकल व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, परिवार का गठन नहीं करता है। वह रहेगा, जो चीजों की प्रकृति में निहित है, एक व्यक्ति, एक अकेला राहगीर जब तक कि उसे कोई साथी नहीं

मिल जाता। एकल व्यक्ति वाला परिवार संदर्भ में एक विरोधाभास है। अधिनियम की धारा 2 (31) एक हिंदू अविभाजित परिवार को एक व्यक्ति से अलग और अलग इकाई के रूप में मानती है और हमारी राय में, उस अंतर को ध्यान में नहीं रखना गलत होगा।"

13. उपरोक्त टिप्पणियाँ किसी भी तरह से प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता के रुख को पुष्ट करती हैं, वास्तव में, उस पर दृढ़ता से बूमरैंग करती हैं। यह इन टिप्पणियों से नहीं मिलता है कि क्योंकि एक व्यक्ति एक परिवार का गठन नहीं कर सकता है, हर दो व्यक्ति एक हिंदू अविभाजित परिवार का गठन करेंगे। वास्तव में मैं इस निर्णय से पहले ही उद्धृत कर चुका हूं जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निर्धारिती एक व्यक्ति था न कि एक परिवार। मैं सी. कृष्ण प्रसाद बनाम सी. आई. टी. एम. ए. एन. यू./एस. सी./0240/1974 में कम से कम विचलन या दरार नहीं पा रहा हूँ:[1974]97 आई. टी. आर. 493 (एस. सी.) और सुरजित लाल छाबड़ा बनाम सी. आई. टी. मनु/एस. सी./0266/1975: [1975] 101 आई. टी. आर. 776 (एस. सी.), और दोनों निर्णय एक तरह से एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों अपीलार्थी राजस्व की सहायता के लिए दृढ़ता से जाते हैं।

14. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, शुरुआत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में प्रस्तुत किया जाता है और यह माना जाता है कि हिंदू कानून द्वारा शासित एक व्यक्तिगत निर्धारिती की स्थिति उसके विवाह पर आयकर अधिनियम के तहत हिंदू अविभाजित परिवार की स्थिति में स्वचालित रूप से नहीं बदलेगी।

15. उपरोक्त के आलोक में, निर्दिष्ट प्रश्न का विशिष्ट उत्तर यह है कि न्यायाधिकरण कानूनी रूप से यह अभिनिर्धारित करने में सही नहीं था कि विवाह के बाद निर्धारिती की स्थिति हिंदू अविभाजित परिवार की थी न कि किसी व्यक्ति की। सवाल का जवाब राजस्व के पक्ष में

और निर्धारिती के खिलाफ दिया जाता है। हालाँकि, तीन संदर्भों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा,

एस.के. झा न्यायमूर्ति

16. मैं पूरी तरह से सहमत हूं।

उदय सिन्हा, न्यायमूर्ति

17. मैं सहमत हूँ।

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।